(ii) Need to take steps to avoid retrenchment of mine workers in Orissa

SHRI LAKSHMAN MALLICK : (Jagatsinghpur) : Iron Ore mining is a traditional economic activity in the State of Orissa. A large number of poor adivasi workers earn their livelihood by working in these mines. But it is a matter of great concern that due to the sharp decline in the export of iron ore from Orissa many iron ore mines are on the verge of closure. This will lead to large scale retrenchment of poor workers. Thousands of them belonging to SC and ST will be thrownout of employment.

I, therefore, request the Government to take the following immediate measures :—

1. Increase procurement from the non-captive mines to 1880-81 level. i.e., 1.72 lakh tonnes per month.

2. Indicate the procurement programme to each individual mineownerso that they are able to plan their production programme in advance.

3. Considering the overall requirement of the steel plants over a period of time and taking into account the fluctuation in demand and supply, a reasonable procurement quantity should be decided.

4. Investment for development of new iron ore mines should not be taken up in view of the capacities already available in the existing mines.

(iii) Need to curb the illegal sale of intoxicants in hilly areas of U.P.

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सन 1977 से सुरा, लिक्विड, वायोटोनिक्स, नकली पदार्थ व कई अन्य प्रकार के मादक पदार्थ अवैध रूप से समाज में बिक रहे हैं। आई० आर० डी० पी० के तेहत प्राप्त आर्थिक सहायता का दुरुपयोग लोग इन मादक पदार्थों को खरीदने में कर रहे हैं। प्रदेश व केन्द्र की सरकार वस्तु-स्थिति को समझते हुए भी कोई ठोस एवं व्यावहारिक हल इस समस्या का नहीं निकाल पा रही है। स्थानीय प्रशासन विभिन्न अधिनियमों के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग इन पदार्थों के विक्रय को रोकने के लिए नहीं कर पा रहा है। समस्त पर्वतीय अचल में इस स्थिति के विरुद्ध व्यापक असंतोष है। स्त्री-पुरुष-नौजवान सब इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। यदि शासन द्वारा इस समस्या के निराकरण के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो सीमान्त क्षेत्रों का यह आन्दोलन गलत स्वरूप ग्रहण कर पृथकतावादी क्षेत्रीय संकीर्ण मनोवृत्ति वाली ताकतों के हाथ में जा सकता है।

अत : मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से दिवेदन है—

1. उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया जाय।

2. नेपाल सीमा से तस्करी से आने वाले मादक द्रव्यों की रोकथाम हेतु व्यापक प्रबन्ध किये जायें।

3. मादक आसवों एवं मृत संजीवनी सुरा एवं अहिफेन्सवा उत्पादक संस्थानों पर प्रभावी उत्पादन नियन्त्रण लागू किया जाय।

4. 10 प्रतिशत से अधिक मादकता वाले पदार्थों को ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के बजाय एक्साइज एक्ट के कार्यक्षेत्र में लाया जाय।